

Privatisation of Education System

706. SHRIMATI URMILABEN HIMANBHAI PATEL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether Government have any plan to extend the policy of privatisation to the education system;

(b) whether Government intend to allow private universities; and

(c) if so, what are the details thereof and the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) There is no proposal to privatise Higher Education, which involves transfer of control, fully or partially, from the State to Private enterprises.

(b) and (c) The Government is agreeable to lay down a legislative framework for establishment of Private Universities in suitable cases. Accordingly, the Private Universities Establishment and Regulation Bill was introduced in Rajya Sabha on 25-8-95. The Bill has been examined by the Standing Committee on Human Resource Development. Government is examining the recommendations of the Committee.

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत आवंटित धनराशियां

707. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या मानव साधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में साक्षरता अभियान के अन्तर्गत तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को आवंटित की गई राशियों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) उपर्युक्त आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि उपर्युक्त अवधि के दौरान जारी की गई,

(ग) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में उक्त योजना अन्तर्गत शामिल किए गए प्राथमिक विद्यालयों का वर्ष-वार प्रतिशत कितना-कितना है, और

(घ) वर्ष 1996-97 में उपर्युक्त अभियान के अन्तर्गत जारी जाने वाली योजनाओं हेतु कितनी धनराशि का अधान रखा गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में सहायक मंत्री (श्री मुही राम सायकिया): (क) साक्षरता मिशन

के अंतर्गत निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अनेक योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 156.31 करोड़ रुपये, 210.00 करोड़ रुपये तथा 131.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए 224.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

देश में प्रदूषण का प्रभाव

708. श्री रामजीलाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) इस समय देश में प्रदूषण के कारण लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारत के विभिन्न शहरों में प्रदूषण, विशेषकर धुआं प्रदूषण की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है;

(ख) क्या सरकार को किसी धुआं शोधक यंत्र के बनाए जाने के बारे में हाल ही में पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आविष्कारकों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री: (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) सरकार को यानीय प्रदूषकों के स्पष्ट कारण और प्रभाव और मानव स्वास्थ्य पर उनका असर से संबंधित किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार "विश्व व्यापी प्रदूषण और स्वास्थ्य" नामक दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि निर्लंबित धूलकणों के स्तर के संबंध में विश्व के 41 शहरों में से दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का स्थान क्रमशः चौथा, छठा और तेरहवां है जबकि सल्फरडाईआक्साइड के संबंध में 54 शहरों में से दिल्ली का 27वां, मुंबई का 18वां और कलकत्ता का 37वां स्थान है। धुएं के संबंध में कोई विशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। यमुनानगर के श्री मामचंद नामक व्यक्ति से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि धुएं के प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने एक उपकरण तैयार किया है।